



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 13, 1973/फाल्गुन 22, 1894
N. 52] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 13, 1973/PHALGUNA 22, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 13th March 1973

SUBJECT.—Exports to the Arab Republic of Egypt and Sudan under Indo-ARE and Indo-Sudan Trade Arrangements.

No. 7-ETC(PN)/73.—Attention of all exporters is invited to Public Notices No. 9(ETC)/PN/71, dated the 17th November, 1971 and No. 18-ETC(PN)/72, dated the 8th September, 1972 wherein procedure for centralised confirmation of letters of Credit for exports to Egypt and registration of contracts for exports to Sudan has been laid down. These instructions are recapitulated for compliance by all exporters:

1. All exports to Arab Republic of Egypt under the Indo-ARE Trade Arrangement should be made only against valid letters of credit reconfirmed by the State Bank of India, Bombay. It should be noted that this reconfirmation of letters of credit by the State Bank of India is to be in addition to the normal confirmation to be given by the bank on which the credit is opened.
2. No shipments to Sudan would be allowed under the Indo-Sudan Trade Arrangement unless the contract is first registered with the State Bank of India, Bombay. The State Bank of India, Bombay will register such contracts on payment of service charges fixed by the Bank. Exporters can have their documents forwarded to State Bank of India, Bombay through any branch of any bank. On registration, the State Bank of India, Bombay will issue to the exporters a certificate which will entitle the latter to effect shipments. Without this certificate no shipments to Sudan would be allowed.

3. It may be noted that under the current Indo-ARE and Indo-Sudan Trade Arrangements there is no provision for new deferred payment contracts. Therefore no new contracts should be entered into for exports to these countries on deferred payment basis.

S. G. BOSE MULICK,

Chief Controller of Imports & Exports,

बाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार निंत्रण

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1973

विषय.—भारत-मिस्र के अरब गणराज्य तथा भारत सूडान व्यापार व्यवस्थाओं के अन्तर्गत मिश्र के अरब गणराज्य तथा सूडान को निर्यात ।

संख्या : 7-ई० टी० सी० (पी०एन०)/73.—सभी निर्यातकों का ध्यान सार्वजनिक सूचना सं० 9-ई०टी०सी० ' (पी० एन०) /71 दिनांक 17 नवम्बर, 1971 और संख्या 18 ई०टी०सी० (पी०एन०)/72 दिनांक 8 सितम्बर, 1972 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिन में मिस्र को निर्यात करने के लिए साख-पत्र केन्द्रीभूत पुष्टिकरण के लिए तथा सूडान को निर्यात करने के लिए संविदाओं के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है । सभी निर्यातकों द्वारा इन अनुदेशों का पालन करने के लिए सार-संक्षेप प्रस्तुत किया जाता है:—

1. भारत-मिस्र के अरब गणराज्य व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत मिस्र के अरब गणराज्य को सभी प्रकार के निर्यात केवल भारत के स्टेट बैंक, बम्बई द्वारा पुनः पुष्ट किए गए वैद्य साख-पत्रों के मद्दे ही किए जाने चाहिए । इसे नोट कर लेना चाहिए कि भारत के स्टेट बैंक द्वारा इस साख पत्र की पुनः पुष्टि बैंक द्वारा दी गई सामान्य पुष्टि के अतिरिक्त है जिसके आधार पर साख-पत्र खोला जाता है ।

2. जब तक भारत के स्टेट बैंक, बम्बई के पास संविदा को प्रथमतः पंजीकृत नहीं करा लिया जाता, भारत-सूडान व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत किसी प्रकार के पोतलदान की स्वीकृति नहीं दी जाएगी । भारत का स्टेट बैंक, बम्बई ऐसी संविदाओं का पंजीकरण बैंक द्वारा निश्चित किए गए सेवा-प्रभारों को चुकता करने पर ही करेगा । निर्यातकों को भारत के स्टेट बैंक, बम्बई को अपने प्रलेखों को किसी भी बैंक की किसी भी शाखा के माध्यम से अग्रसारित करना है । पंजीकरण हो जाने पर, भारत का स्टेट बैंक, बम्बई निर्यातकों को एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा जो उनको बाद में पोतलदान करने का अधिकारी बनाएगा । बिना इस प्रमाण-पत्र के सूडान को किसी भी प्रकार के पोतलदान करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।

3. इसे जान लिया जाए कि वर्तमान भारत-मिस्र के अरब गणराज्य तथा भारत-सूडान व्यापार व्यवस्थाओं के अन्तर्गत नई पश्च भुगतान संविदाओं के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है । इसलिए, पश्च भुगतान के आधार पर इन देशों को निर्यात करने के लिए कोई नई संविदा नहीं की जाएगी ।

एम० जी० बोस मलिक

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।